



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 3, 2018/माघ 14, 1939

No. 46]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 3, 2018/MAGHA 14, 1939

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 25 जनवरी, 2018

सं. टीएएमपी/5/2018-एमबीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48.49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा मुम्बई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) से 21 जून, 2016 के आदेश संख्या टीएएमपी/78/2015-एमबीपीटी के द्वारा अनुमोदित अपने वर्तमान दरमानों के संशोधन के रूप में पत्तन सीमाओं के नये समतुल्यों के साथ पत्तन लाईटरेज लंगरगाह (पी एल ए) से सम्बंधित टिप्पणी के संशोधन के लिये प्राप्त प्रस्ताव का इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या. टीएएमपी/5/2018-एमबीपीटी

मुम्बई पत्तन न्यास

- - -

आवेदक

गणपूर्ति

- (i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(जनवरी, 2018 के 19वें दिन पारित)

यह मामला मुम्बई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) से 21 जून, 2016 के आदेश संख्या टीएएमपी/78/2015-एमबीपीटी के द्वारा अनुमोदित अपने वर्तमान दरमानों के संशोधन के रूप में पत्तन सीमाओं के नये समतुल्यो के साथ पत्तन लाईटरेज लंगरगाह (पी एल ए) से सम्बंधित टिप्पणी के संशोधन के लिये प्राप्त प्रस्ताव से सम्बंधित है।

2. प्राधिकरण ने 21 जून, 2016 के आदेश संख्या टीएएमपी/78/2015-एमबीपीटी के द्वारा एमबीपीटी के दरमान अनुमोदित किये थे। उक्त आदेश के अनुसार अध्याय 2 – पोत सम्बंधी प्रभार के अंतर्गत खंड 2.15(क) में निम्न टिप्पणी निर्धारित की गयी थी :-

“टिप्पणी : पत्तन लाईटरेज लंगरगाह क्षेत्र में निम्नलिखित समतुल्य सम्मिलित है:

बिंदु क – अक्षांश 18° 57' एन रेखांश 72° 41' ई

बिंदु ख - अक्षांश 18° 55' एन रेखांश 72° 41' ई

बिंदु 'ग' - अक्षांश 18° 55' एन रेखांश 72° 43.5' ई

बिंदु 'घ' - अक्षांश 18° 55' एन रेखांश 72° 43.5' ई”

3.1. इस पृष्ठभूमि में एमबीपीटी ने अपने प्रस्ताव में पत्तन अनुसूची 2.15(क) के नीचे की टिप्पणी को पत्तन सीमाओं के नये विस्तारित समतुल्यो द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव किया है। एमबीपीटी द्वारा रखे गये मुख्य मुद्दों का सारांश इस प्रकार है :

- (i). बोर्ड ने 28/09/2016 के टीआर संख्या 68 के द्वारा वर्तमान एमबीपीटी पत्तन सीमाओं के पश्चिम की ओर विस्तार करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी और मंत्रालय को 24.10.2016 के पत्र के द्वारा सूचित किया गया था। तदनुसार पोत परिवहन मंत्रालय ने 20.04.2017 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 1170 द्वारा मुम्बई पत्तन सीमा का विस्तार करने की अधिसूचना जारी की और इसका पश्चिम की ओर और विस्तार करते हुए इस संबंध में भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग - II, खंड 3, उप-खंड (iii) में 20.04.2017 को प्रकाशित किया।
- (ii). सभी संबंधितों और सभी पत्तन प्रयोक्ताओं को 03 जून 2017 के परिपत्र के द्वारा सूचित किया गया था की कोई भी परिचालन करने के लिए पत्तन की विस्तारित सीमा के भीतर प्रवेश करने वाले पोतों को 27.04.2017 से पत्तन के दरमानों के अंतर्गत लागू सभी पत्तन प्रभार देने होंगे !
- (iii). चूंकि वर्तमान पत्तन सीमा में विस्तार किया गया है, पत्तन लाईटरेज लंगरगाह क्षेत्र को नई पश्चिम की ओर पत्तन सीमा का विस्तार किया जाना है। इस प्रकार पत्तन निम्न समतुल्यो द्वारा बद्ध होगा:

बिंदु 'क' – अक्षांश 18° 57' एन रेखांश 72° 37' ई

बिंदु 'ख'- अक्षांश 18° 55' एन रेखांश 72° 37' ई

बिंदु 'ग'- अक्षांश 18° 55' एन रेखांश 72° 43.5' ई

बिंदु 'घ' - अक्षांश 18° 57' एन रेखांश 72° 43.5' ई “

- (iv). 2.15(क) के नीचे की टिप्पणी को उक्त संशोधित समतुल्यों से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है। एमबीपीटी के दरमानों के अंतर्गत लागू सभी पत्तन प्रभार उन पोतों पर भी लागू करने का प्रस्ताव है जो विस्तारित पत्तन क्षेत्र में कार्गो प्रचालन करेंगे।

3.2. एमबीपीटी ने प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं:

- (i). 28.09.2016 का एमबीपीटी बोर्ड का संकल्प संख्या 68.
- (ii). विस्तारित पत्तन सीमा की 20.04.2017 की सरकार की अधिसूचना कि प्रति
- (iii). विस्तारित पत्तन सीमा का नक्शा
- (iv). एमबीपीटी द्वारा जारी 03.06.2017 के व्यापार परिपत्र की प्रति

4. मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट से प्राप्त जानकारी की कुलता के संदर्भ से, निम्नलिखित स्थिति उभर कर सामने आती है:

- (i). अपने प्रस्ताव के साथ एमबीपीटी द्वारा भेजी गई मुम्बई पत्तन न्यास के न्यासी मंडल की बैठक से संबंधित कार्यवाही की प्रति से यह देखा गया है कि स्ट्रीम परिचालनो के लिये एमबीपीटी आने वाले पोतो का आकार पिछले कुछ वर्षों में बढ़ गया है। वर्तमान प्रवृत्ति कार्गो को बड़े पोतो में मूव करने की है ताकि किफायती दर प्राप्त की जाये और परिवहन लागत को घटाया जा सके। ऐसे पोतो का ड्राफ्ट लगभग 20 मीटर बताया जाता है। चूंकि मुम्बई पत्तन पर पत्तन लाईट्रेज लंगरगाह की वर्तमान उपलब्ध गहराई ऐसे पोतो के लाईट्रेज परिचालनो के लिये लिये पर्याप्त नहीं होती, एमबीपीटी ने पत्तन सीमा का विस्तार उस हद तक करने की आवश्यकता को महसूस किया जहाँ औसत गहराई 21.5 मीटर उपलब्ध हो। इस पृष्ठभूमि में एमबीपीटी ने पत्तन सीमा का विस्तार करने का निर्णय लिया है।
- (ii). एमबीपीटी के न्यासी मंडल के अनुमोदन के आधार पर पोत परिवहन मंत्रालय (एम ओ एस) ने एमबीपीटी की पत्तन सीमाओं के समतुल्यों के संशोधन का अनुमोदन किया और इसे 27 04.2017 की राजपत्र अधिसूचना संख्या राद्दा 1170 अधिसूचित किया। परिणामस्वरूप, एमबीपीटी ने इस प्राधिकरण को अपने वर्तमान दरमानो में यथानिर्धारित पत्तन लाईट्रेज लंगरगाह (पी एल ए) के वर्तमान समतुल्यों का एमओएस द्वारा अनुमोदित और अधिसूचित संशोधित समतुल्यो के साथ प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव किया। वर्तमान दरमानो के अनुसार समतुल्यौ और एमबीपीटी द्वारा यथाप्रस्तावित संशोधित समतुल्यौ कि तुलनात्मक स्थिति नीचे सारणीबद्ध की गयी है:

	वर्तमान दरमानो के अनुसार		एमओएस द्वारा अनुमोदित के अनुसार प्रस्तावित	
बिंदु 'क'	अक्षांश 18° 57' एन	रेखांश 72° 41' ई	अक्षांश 18° 57' एन	रेखांश 72° 37' ई
बिंदु 'ख'	अक्षांश 18° 55' एन	रेखांश 72° 41' ई	अक्षांश 18° 55' एन	रेखांश 72° 37' ई
बिंदु 'ग'	अक्षांश 18° 55' एन	रेखांश 72° 41' ई	अक्षांश 18° 55' एन	रेखांश 72° 43.5' ई
बिंदु 'घ'	अक्षांश 18° 57' एन	रेखांश 72° 41' ई	अक्षांश 18° 57' एन	रेखांश 72° 43.5' ई

- (iii). प्रशुल्क नीति 2015 का खंड 5.4 अनुबद्ध करता है कि यदि किसी प्रस्ताव या मामले में प्रयोक्ताओं से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो इस प्राधिकरण को कोई सँयुक्त सुनवाई आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तुत मामले में एमबीपीटी ने सभी पत्तन प्रयोक्ताओं को एमबीपीटी की पत्तन सीमाओं के विस्तार के बारे में सूचित करते हुए 03 जून 2017 को व्यापार परिपत्र जारी किया और सभी संबंधित प्रयोक्ताओं को सूचित किया कि कोई भी परिचालन करने के लिये पत्तन की विस्तारित सीमा के भीतर प्रवेश करने वाले पोतो को पत्तन के दरमानो के अंतर्गत लागू सभी पत्तन प्रभार देने होंगे। एमबीपीटी ने परिपत्र जारी करने के बाद 7 महीने बीत जाने तक भी यह सूचित नहीं किया कि क्या किसी प्रयोक्ता ने आपत्ति तो नहीं की है। यहाँ तक कि हमने भी किसी

प्रयोक्ता / प्रयोक्ता संगठन से पत्तन की सीमा के विस्तार और विस्तारित सीमाओं तक पत्तन में लागू सभी पत्तन प्रभार देने के बारे में कोई सूचना मिली है। किसी प्रयोक्ता / प्रयोक्ता संगठन से कोई विशेष आपत्ति न होने पर, यह महसूस किया गया कि संदर्भित मामले में किसी परामर्शी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है।

- (iv). यहाँ यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि पत्तन ने पत्तन की सीमाओं के विस्तार विस्तारित पत्तन सीमाओं तक 21 जून 2016 के आदेश द्वारा अनुमोदित दरमानों में लागू पत्तन प्रभारों की उगाही से होने वाले पत्तन के वार्षिक राजस्व प्रतिफल (ए आर आर) पर पड़ने वाले राजस्व प्रभाव की सूचना नहीं दी है। प्रस्तावित संशोधन से कुछ वित्तीय प्रभाव तो पड़ेगा ही क्योंकि एमबीपीटी विस्तारित पत्तन क्षेत्र में कार्गो परिचालन के लिये पोतों पर लंगरगाह शुल्क की उगाही से अतिरिक्त राजस्व अर्जित करेगा। चूंकि प्रस्ताव से एमबीपीटी को अर्जित की होने वाली कथित अतिरिक्त आय का 2016 में एमबीपीटी के दरमान के सामान्य संशोधन प्रस्ताव का निर्णय लेते समय पूर्वानुमान नहीं लगाया गया था, ऐसा भी हो सकता है कि राजस्व की तटस्थ स्थिति बनाये रखने के लिये कोई और दर समायोजित की जानी चाहिये। इस संबंध में यहाँ यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि, तटस्थ स्थिति सुनिश्चित रखने का प्रश्न तब उठता है जब किसी पत्तन को, एआर आर कवर करने के लिये, पहले ही वह प्रशुल्क दे दिया गया हो जो उसे संदेय था, और तत्पश्चात् उसे फिर से नया प्रशुल्क मंजूर कर दिया जायेगा। लेकिन, एमबीपीटी के मामले में, यह स्मरण कराना संगत है कि जून 2016 में निपटाये गये एमबीपीटी के सामान्य प्रशुल्क संशोधन से संबंधित आदेश में 1572.19 करोड़ रुपये के अधिकतम सूचकांकित वार्षिक राजस्व प्रतिफल (एआरआर) के प्रति एमबीपीटी द्वारा प्रशुल्क के प्रस्तावित स्तर पर यथा आकलित राजस्व आकलन मात्र 1306.64 करोड़ रुपये था, इस प्रकार पत्तन द्वारा 265.55 करोड़ रुपये के राजस्व का अंतर अनकवर्ड छोड़ दिया गया। इसलिए संदर्भाधीन प्रस्ताव के हवाले से अर्जित अतिरिक्त राजस्व प्रशुल्क चक्र के दौरान इस राजस्व अंतर को पाट लिया जायेगा। इसलिये, राजस्व की तटस्थ स्थिति बनाये रखने के लिये किसी अन्य दर के समायोजन का प्रश्न नहीं उठता।
- (v). यह देखते हुए कि पोत परिवहन मंत्रालय ने पत्तन की सीमाओं का पश्चिम की ओर विस्तार को अनुमोदित किया है और कि एमबीपीटी के प्रस्ताव को न्यासी मंडल का अनुमोदन प्राप्त है और किसी प्रयोक्ता/प्रयोक्ता संगठन से एमबीपीटी द्वारा व्यापार के पत्तन की सीमा के परिवर्तन की अधिसूचना कि सूचना का परिपत्र जारी करने के 7 महीने बीत जाने के बाद भी कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, यह प्राधिकरण एमबीपीटी के प्रस्ताव को अनुमोदित करने को प्रवृत्त है।
- (vi). महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 48 के अंतर्गत सूचीबद्ध सेवाओं के लिये प्रभारों को शासित करने वाली सोपाधिकतायों में परिवर्तन या आशोधन करने के लिये इस प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है। एमबीपीटी द्वारा किये गये निवेदन से यह पता चलता है कि एमबीपीटी ने, पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा पत्तन की विस्तारित सीमाओं की अधिसूचना के पश्चात्, 05 जनवरी, 2018 को अपना प्रस्ताव दायर करने से काफी पहले व्यापार परिपत्र जारी करके 27 अप्रैल, 2017 से एमबीपीटी विस्तारित सीमाओं पर दरों को पहले ही लागू कर चुका है। इस प्रकार एमबीपीटी ने 27 अप्रैल 2017 से प्रभावी प्रस्तावित संशोधन की सम्पन्न कार्य स्थिति को अनुमोदन प्राप्ति के लिये इस प्राधिकरण को प्रस्तुत किया है। एक पत्तन से यह प्रत्याशा करना अनुचित नहीं है कि वह प्रशुल्क के आशोधन या दरमानों की सोपाधिकतायों के आशोधन के लिये समय पर इस प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्ति के लिये तत्काल कार्रवाई करे।

(vii). जब तक संबंधित आदेश में विशेष रूप से अन्यथा व्यवस्था न की गई हो इस प्राधिकरण के आदेश सामान्यतः राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के पश्चात् उत्तर व्यापी प्रभाव से लागू होते हैं। आपवादिक मामलों में, लिखित में अभिलेखबद्ध कारणों से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाता है। संदर्भित मामले में, 27 अप्रैल, 2017 से कार्यान्वित करने वाले व्यापार परिपत्र से प्रयोक्ताओं को कोई आपत्ति नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए यह प्राधिकरण पत्तन सीमाओं के नये समतुल्यो के साथ पत्तन लाईटरेज लंगरगाह (पी एल ए) से सम्बंधित टिप्पणी के संशोधन और 27 अप्रैल, 2017 से प्रभावी विस्तारित पत्तन क्षेत्र में दरों के कार्यान्वयन के अनुमोदन देने को प्रवृत्त है। तथापि, एमबीपीटी को सलाह दी जाती है कि वह प्रस्तावित परिवर्तनों को इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन दिये जाने से पूर्व दरमानों में परिवर्तन की सूचना व्यापार परिपत्र जारी करके न दे।

5.1. परिणाम में, और ऊपर दिये गये कारणों से, तथा सामूहिक विचार विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण अध्याय 2 – लंगरगाह सम्बंधी प्रभारों की अनुसूची के अंतर्गत 2.15(क) में वर्तमान टिप्पणी को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करने का अनुमोदन करता है :-

“टिप्पणी : पत्तन लाईट्रेज लंगरगाह क्षेत्र में निम्नलिखित समतुल्य सम्मिलित है :

बिंदु 'क'	अक्षांश 18° 57' एन	रेखांश 72° 37' ई
बिंदु 'ख'	अक्षांश 18° 55' एन	रेखांश 72° 37' ई
बिंदु 'ग'	अक्षांश 18° 55' एन	रेखांश 72° 43.5' ई
बिंदु 'घ'	अक्षांश 18° 57' एन	रेखांश 72° 43.5' ई

”

5.2. एमबीपीटी को उक्त उपबंधों को दरमानों में अंतर्विष्ट करने की सलाह दी जाती है।

5.3. टिप्पणी में उक्त संशोधन को 27 अप्रैल, 2017 से प्रभावी समझा जाता है और इसकी वैधता एमबीपीटी के वर्तमान दरमानों की 31 मार्च, 2019 को समाप्त वैधता के साथ सह-समाप्य समझी जायेगी।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./415/17]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 25th January, 2018

No. TAMP/5/2018-MBPT.—In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Mumbai Port Trust (MBPT) for amendment to a note relating to Port Lighterage Anchorage (PLA) area with new extended co-ordinates of port limits, as a modification to its existing Scale of Rates approved vide Order No.TAMP/78/2015-MBPT dated 21 June 2016, as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/5/2018-MBPT

The Mumbai Port Trust

- - -

Applicant

QUORUM

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 19th day of January 2018)

This case relates to the proposal received from Mumbai Port Trust (MBPT) for amendment to a note relating to Port Lighterage Anchorage (PLA) area with new extended co-ordinates of port limits, as a modification to its existing Scale of Rates approved vide Order No.TAMP/78/2015-MBPT dated 21 June 2016.

2. This Authority vide its Order No. TAMP/78/2015-MBPT dated 21 June 2016 has approved the Scale of Rates of MBPT. Vide the said Order, the following note has been prescribed under section 2.15(A) – Schedule of Anchorage charges under Chapter – II – Vessel Related Charges:

“Note: Port Lighterage Anchorage area encompasses the following co-ordinates:

Point ‘A’- Latitude 18° 57’ N Longitude 72° 41’ E
 Point ‘B’- Latitude 18° 55’ N Longitude 72° 41’ E
 Point ‘C’- Latitude 18° 55’ N Longitude 72° 43.5’ E
 Point ‘D’- Latitude 18° 55’ N Longitude 72° 43.5’ E

- 3.1. In this backdrop, the MBPT has submitted a proposal to replace the note below the schedule 2.15 (A) by the new extended co-ordinates of port limits. The main points made by the MBPT in its proposal are summarized below:

- (i). The Board by TR no. 68 dated 28.09.2016 accorded sanction to the proposal of extension of existing MBPT Port limits westward and the Ministry was informed vide letter dated 24.10.2016. Accordingly, the Ministry of Shipping vide Gazette Notification No. 1170 dated 20.04.2017 has issued a notification extending port limit of Mumbai thereby extending it further westward and has published the same in the official Extra Ordinary Gazette Part-II Section-3 Sub Section (ii) dated 20.04.2017.
- (ii). All concerned and all Port Users were informed vide circular dated 03 June 2017 that vessels entering the extended port limit for carrying out any operations shall be liable to pay all port charges as applicable under the Port Scale of Rates with effect from 27.04.2017.
- (iii). Since the existing port limits have been extended, Port Lighterage Anchorage (PLA) area is to be extended upto the new westward port limit. Thus PLA will be bound by following co-ordinates:

Point ‘A’- Latitude 18° 57’ N Longitude 72° 37’ E
 Point ‘B’- Latitude 18° 55’ N Longitude 72° 37’ E
 Point ‘C’- Latitude 18° 55’ N Longitude 72° 43.5’ E
 Point ‘D’- Latitude 18° 57’ N Longitude 72° 43.5’ E

- (iv). It is proposed to replace the Note below 2.15 (A) by the above revised co-ordinates. It is also proposed to levy all port charges as applicable under the Scale of Rates of MBPT to the vessels which carry out cargo operations at the extended port area.

- 3.2. The MBPT has furnished the following documents along with the proposal:

- (i). MBPT Board Resolution No. 68 of 28.09.2016.
- (ii). Copy of Government Notification of Extended Port Limit dated 20.04.2017.
- (iii). Map of Extended Port Limit.

(iv). Copy of Trade Circular dated 03.06.2017 issued by MBPT.

4. With reference to the totality of the information received from the MBPT, the following position emerges:

- (i). It is seen from the copy of the proceedings relating to the Meeting of the Board of Trustees of Mumbai Port Trust (MBPT) furnished by MBPT along with its proposal, that the size of the vessels that call MBPT for stream operation has increased over a period of few years. The current trend is to move the cargo in bigger vessels so as to achieve economy of scale and reduce transportation cost. Such vessels are reported to have a draft of about 20 Meters. Since the present depth available at Port Lighterage Anchorage is not sufficient for such vessels to call at Mumbai Port for Lighterage operation, the MBPT has felt the need to extend the port limit where the average depth of about 21.5 meters will be available. In this backdrop, the MBPT has decided to extend the port limit.
- (ii). Based on the approval of Board of Trustees of MBPT, the Ministry of Shipping (MOS) has approved the revised co-ordinates of port limits of MBPT and has notified it in the Gazette of India vide notification no. 1170 dated 27 April 2017. Consequently, the MBPT has approached this Authority with a proposal to replace the existing co-ordinates of Port Lighterage Anchorage (PLA) area as prescribed in its existing Scale of Rates, with the revised co-ordinates approved and notified by the MOS. A comparative position of the co-ordinates as per existing SOR and revised co-ordinates as proposed by MBPT is tabulated below:

	As per Existing SOR		Proposed as per the MOS Approval	
Point A	Latitude 18° 57' N	Longitude 72° 41' E	Latitude 18° 57' N	Longitude 72° 37' E
Point B	Latitude 18° 55' N	Longitude 72° 41' E	Latitude 18° 55' N	Longitude 72° 37' E
Point C	Latitude 18° 55' N	Longitude 72° 41' E	Latitude 18° 55' N	Longitude 72° 43.5' E
Point D	Latitude 18° 57' N	Longitude 72° 41' E	Latitude 18° 57' N	Longitude 72° 43.5' E

- (iii). Clause 5.4 of the Tariff Policy, 2015 stipulates that in case there are no objections from users for a proposal or a case, this Authority need not organize any joint hearing. In the instant case, the MBPT has issued the trade circular dated 03 June 2017 intimating concerned port users with regard to Extension of Port's Limits of MBPT and informing the concerned users to note that vessels entering the extended Port's limit for carrying out any operations shall be liable to pay all Port Charges as applicable under the Port Scale of Rates. The MBPT has not reported about any user objecting to the said circular even after passage of 7 months i.e. from the date of issue of circular. Even we are not in receipt of any communication from any of the users / user organisations objecting to the extension of port limits and the applicability of the Port Scale of Rates to the extended limits. Since there is no objection from any of the users/ user organisations, it is felt that no consultative process is necessary in the case in reference.
- (iv). It is relevant to mention here that the Port has not furnished about the revenue impact on the Annual Revenue Requirement (ARR) considered in approving the existing SOR vide Order dated 21 June 2016 of the Port arising on account of extension of port limits and levy of the Port Scale of Rates in the extended port limits. The proposed amendment would involve some financial implication, as MBPT may earn additional revenue on account of levy of the Anchoarge Fee to the vessels which carry out cargo operations at the extended port limit. Since the said additional income to be earned by MBPT from the proposal had not been anticipated and factored while deciding the general revision of SOR of MBPT decided in 2016, there may be a view that some other rate should be adjusted to maintain revenue neutral position. In this regard, it is relevant here to mention that the question of ensuring a revenue neutral position arises when a port has already been given tariff whatever is due to it, to cover the ARR and thereafter it is to be again granted a new tariff. However, in the case of MBPT, it is relevant to recall that in the Order relating to the MBPT general revision case disposed in June 2016, as against the Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement (ARR) of ₹.1572.19 crores, the Revenue Estimation at the proposed level of tariff as worked out by MBPT was only ₹.1306.64 crores, thereby leaving a revenue gap of ₹.265.55 crores left uncovered by the Port. Therefore, the anticipated additional revenue to be generated on account of the proposal in reference during the remaining tariff cycle may be subsumed in the revenue gap. Therefore, the question of adjustment in some other rate to maintain revenue neutral position does not arise.
- (v). Given that the Ministry of Shipping has approved the extended port limits westwards and the proposal of the MBPT has the approval of its Board of Trustees and since no objections have been received from

any users / user organisations even after a lapse of 7 months from the day of issue of Trade Circular by MBPT intimating about notification of change in port limits, this Authority is inclined to accord approval to the proposal of the MBPT.

- (vi). Levy of charges or modification to the conditionalities governing the application of charges for the services listed under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963, requires approval of this Authority. From the submissions made by MBPT it is noticed that the MBPT, after notification of the extended Port Limits by the MOS, has already implemented the rates at the extended port limit of MBPT with effect from 27 April 2017 by way of issue of a Trade Circular much prior to filing its proposal on 05 January 2018. Thus, the MBPT has sought approval to the proposed amendment with effect from 27 April 2017 presenting a fait accompli situation to this Authority. It is not unreasonable to expect a port to take immediate timely action to seek approval of this Authority for modification of tariff or modification to the conditionalities prescribed in the Scale of Rates.
- (vii). Orders of this Authority generally come into effect prospectively after expiry of 30 days from the date of Gazette Notification unless otherwise different arrangement is specifically mentioned in the respective tariff Orders. In exceptional cases, retrospective effect is given for reason to be recorded. In the case in reference, there is no objection from the users for the Trade Circular implemented with effect from 27 April 2017. In view of this position, this Authority is inclined to grant approval for amendment to note relating Port Lighterage Anchorage (PLA) area with new extended co-ordinates of port limits and to implement the rates at extended port area with effect from 27 April 2017. However, the MBPT is advised to refrain from issuing Circulars to Trade intimating about change in the Scale of Rates and conditions, prior to this Authority according approval to the proposed changes.

5.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority accords approval to replace the existing note under Schedule 2.15 (A) – Schedule of Anchorage charges under Chapter II with the following :

“Note: Port Lighterage Anchorage area encompasses the following co-ordinates :

Point A	Latitude 18° 57' N	Longitude 72° 37' E
Point B	Latitude 18° 55' N	Longitude 72° 37' E
Point C	Latitude 18° 55' N	Longitude 72° 43.5' E
Point D	Latitude 18° 57' N	Longitude 72° 43.5' E

”

5.2. The MBPT is advised to suitably incorporate the above provision in its Scale of Rates.

5.3. The said amendment to the note is deemed to have come into effect from 27 April 2017 and its validity shall remain co-terminus to the validity of the existing Scale of Rates of MBPT upto 31 March 2019.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. –III/4/Exty./415/17]